नवसर्जन संस्कृति

RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 300
दि. 03.03.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

रेवेन्यू केसों को निपटाने में लखनऊ नंबर वन, जिला कोर्ट में जौनपुर ने फिर मारी बाजी

लखनऊ सबसे अधिक राजस्व मामले निस्तारित करने में अव्वल रहा है। वहीं, जिला कोर्ट में जौनपुर ने एक बार फिर बाजी मारी है। जौनपुर 15 माह से टॉप 5 में बना है।

लखनऊः , (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू केसों को निपटाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशेष जोर दिया है। उनके निदेर्शों का असर है कि इन केसों को तेजी से निस्तारित किया जा रहा है। मामलों की मुख्यमंत्री के स्तर पर मॉनीटरिंग हो हो रही है। राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण की दिशा में मुख्यमंत्री की सख्त मॉनीटरिंग का असर साफ दिख रहा है। हर माह जिलावार मामलों की समीक्षा होती है। राजस्व कोर्ट कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (RCCMS) की फरवरी माह की रिपोर्ट में पूरे प्रदेश में सबसे अधिक राजधानी लखनऊ में मामलों को निस्तारित किया गया है। वहीं, जिला स्तरीय कोर्ट में राजस्व के मामले निपटाने में एक बार फिर जौनपुर ने बाजी मारी है। जिला स्तरीय कोर्टों में राजस्व वादों के निस्तारण में पिछले 15 माह से जौनपुर टॉप फाइव जिलों में बना हुआ है।

राजधानी में सबसे अधिक मामले निस्तारित

योगी आदित्यनाथ सरकार की विशेष पहल के तहत तेजी से मामलों के निपटारे की रणनीति को अपनाया गया। इससे राजस्व विवादों के मामलों में बड़ा सुधार देखने को मिला है। नतीजा पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश भर में राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी है। सीएम के स्पष्ट निर्देश हैं कि राजस्व विवादों के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाए। उनकी इस पहल का उद्देश्य न केवल जनता को त्वरित न्याय दिलाना है, बल्कि प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को भी बढ़ावा देना है।

सीएम योगी के निर्देश के तहत प्रदेश के डीएम और अन्य संबंधित अधिकारी पूरी तत्परता से मामलों का निस्तारण कर रहे हैं।

राजस्व परिषद की आरसीसीएमएस की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी में पूरे प्रदेश में कुल 3,34,538 राजस्व मामलों का निस्तारण किया गया। लखनऊ के डीएम विशाख जी अय्यर ने बताया कि सबसे अधिक राजधानी लखनऊ में 15,981 मामले निस्तारित किए गए। डीएम ने कहा कि यह पूरे प्रदेश में सबसे अधिक हैं। इसके बाद प्रयागराज में कुल 14,132 मामलों को निस्तारित कर पूरे प्रदेश में दूसरा, आजमगढ़ 9333 मामलों को निस्तारित कर तीसरे स्थान पर है।

लखनऊ में सबसे अधिक 15,981 राजस्व मामलों को निपटया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के तहत राजस्व मामलों को प्रमुखता के साथ निपटाया जा रहा है।

राजस्व मामले सर्वोच्च प्राथमिकता

आजमगढ़ डीएम रविंद्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप राजस्व मामलों के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। जन शिकायतों के समयबद्ध समाधान के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रहीं हैं। रेवेन्यू कोर्ट में लंबित प्रकरणों को अभियान चलाकर निपटाया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि आजमगढ़ ने फरवरी में राजस्व मामलों के निस्तारण में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह जौनपुर ने 8912 मामले निस्तारित कर चौथा और बाराबंकी ने 8378 मामलों का निस्तारण कर पांचवां स्थान प्राप्त किया है।

जिला कोर्ट में जौनपुर ने मारी बाजी

जौनपुर डीएम डॉ. दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुसार राजस्व मामलों को निस्तारित किया जा रहा है। बोर्ड ऑफ रेवन्यू की फरवरी माह की राजस्व कोर्ट कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार जौनपुर की पांच राजस्व कोर्टों ने बोर्ड के निर्धारित मानक के निस्तारण से अधिक मामलों का निस्तारण किया है। जौनपुर की पांच राजस्व कोर्टों ने बोर्ड के प्रति माह निस्तारण के मानक 250 से दोगुने से अधिक 542 मामलों का निस्तारण किया है। इसका अनुपात 216.80 प्रतिशत है।

हर कपल की यात्रा एक जैसी नहीं होती

डीएम ने कहा कि इसी के साथ जिला कोर्ट में राजस्व मामलों के निस्तारण में प्रदेश में जौनपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं, मानक 300 के सापेक्ष 381 मामलों का निस्तारण कर दूसरे स्थान पर बस्ती और मानक 300 के सापेक्ष 353 मामले निस्तारित कर तीसरे स्थान पर प्रतापगढ़ है। इसी तरह फरवरी में जौनपुर के जिलाधिकारी कोर्ट ने निर्धारित 30 मामलों के मानक के मुकाबले 86 मामलों का निस्तारण कर 286.67 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की।

सिविल सेवाओं से भर्ती हुए और एलबीएसएनएए में 128वें प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों ने राष्ट्रपति से भेंट की

राज्य सिविल सेवाओं से भर्ती हुए और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) में आयोजित 128वें प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने आज (2 मार्च, 2026) राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।

राष्ट्रपति ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब उन पर जिला या राज्य स्तर की प्राथमिकताओं से कहीं अधिक व्यापक जिम्मेदारियां हैं। इन व्यापक जिम्मेदारियों के लिए विभागीय सीमाओं से परे एक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो प्रशासनिक बाधाओं को दूर करे। सहयोगात्मक रूप से कार्य करके वे संस्थागत सामंजस्य बढ़ा सकते हैं और शासन-तंत्र को सुदृढ़ कर सकते हैं।

मिसाइल हमलों में फंसे 310 यात्री अबू धाबी से दिल्ली सुरक्षित पहुंचे, परिवार को देख छलके खुशी के आंसू

नई दिल्ली, (एजेंसी)।

अबु धाबी से सोमवार को एतिहाद एयरवेज की एक उड़ान 310 यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंची। ये यात्री ईरान के खाड़ी देशों पर मिसाइल व ड्रोन हमलों के कारण वहीं फंसे थे। ईरान ने ये हमले शनिवार से हुए अमेरिका-इजरायल मिसाइल हमलों की जवाबी कार्रवाई में किए थे।

यह उड़ान सोमवार रात 8:30 बजे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 पर उतरी। यात्रियों के बाहर आते ही उनके परिजन उन्हें गले लगाने के लिए दौड़ पड़े। हवाई अड्डे पर बेहद भावनात्मक माहौल था, जहां कई परिवारों का पुनर्मिलन हुआ।

55 वर्षीय विनोद शर्मा ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया, "मेरा बेटा शिव शनिवार को मैनचेस्टर से अबू धाबी के रास्ते लौट रहा था पर वहीं फंस गया। हम बेहद डरे थे, क्योंकि उसने बताया कि उसे होटल के ऊपर मिसाइलें इंटरसेप्ट होते दिखीं और सुनीं। हमने उड़ान लगातार ट्रैक की और भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही राहत महसूस की।"

टर्मिनल पर इंतजार कर रहीं 50 वर्षीय दानिश्ता परवीन ने अपनी बेटी (एतिहाद क्रू मेंबर) के बारे में बताया, "वह वैसे तो 28 फरवरी को आने वाली थी, पर आ नहीं सकी... उसने हमें बताया कि मिसाइलों के कारण हवाई अड्डे की दीवारें हिलती महसूस हुईं। कल उसका जन्मदिन है, तो मैं खुश हूँ कि वह लौट आई है और अब हमारे साथ इसे मना पाएगी।"

अपने बेटे और बहू के साथ लौटीं 52 वर्षीय शशि परमार ने घर पहुंचकर खुशी जताई। उन्होंने कहा, "हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था क्या होगा, और हम बहुत लंबे समय तक वहीं फंसे रहने को लेकर चिंतित थे। बच्चों के साथ दिल्ली में आकर मुझे राहत मिली है; पिछले दो दिनों में पहली बार अब मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूँ।"

42 वर्षीय राहुल कुमार को 28 फरवरी को उड़ान भरनी थी, हवाई अड्डे पर उन्हें बोर्डिंग पास भी मिल गया था। पर ईरान के मिसाइल हमलों के कारण अधिकारियों को विमानों को खड़ा करना पड़ा।

कुमार ने बताया, "मुझे 28 तारीख को ही वापस लौटना था, मेरा बोर्डिंग पास भी तैयार था, पर फ्लाइट निलंबित कर दी गई। इसके बाद हमने आसमान में कई बार मिसाइलों को इंटरसेप्ट होते देखा। हमें अपने होटल पर उन्हीं से गिरता मलबा भी महसूस हुआ, जो मेरे परिवार और मेरे लिए बहुत डरावना था।"

कनाडा से लौट रहीं 50 वर्षीय हरपिंदर सिद्धू अबू धाबी में स्टॉपओवर पर फंस गई थीं।

उनका कहना था, "हमने मिसाइलों की आवाज भी सुनी, पर अधिकारियों ने घबराहट को फैलने नहीं दिया।" अन्य यात्रियों ने भी मुश्किल हालात में सहजता बनाए रखने के लिए अधिकारियों की प्रशंसा की। 32 वर्षीय प्रज्वल वर्मा भी टोरंटो से दिल्ली की यात्रा कर रहे थे, पर उनकी उड़ान रद्द हो गई थी। उन्होंने साझा किया, "हमने कुछ बार मिसाइलों की आवाज सुनी और डर गए थे।

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, 'शंकराचार्य महाराज अगर लखनऊ आते हैं तो राम भक्त...'

केशव प्रसाद मौर्य ने गौ रक्षा पर कहा कि यूपी में गौ-माता को राज्य माता का दर्जा देने की जहां तक बात है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है.

वाराणसी, (एजेंसी)। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के लखनऊ आह्वान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत तेजी से करवट बदल रही है. प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा, 'जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज यदि लखनऊ आते हैं तो एक राम भक्त होने के नाते उनका स्वागत करेंगे.' वहीं उन्होंने गौ रक्षा पर जारी सवाल-जबाब पर कहा कि यूपी में गौ-माता को राज्य माता का दर्जा देने की जहां तक बात है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है.

केशव प्रसाद मौर्य सोमवार को वाराणसी दौरे पर थे, जहां उन्होंने यह बयान पत्रकारों से बातचीत में दिया. उन्होंने यूपी में गौ-रक्षा के सवाल पर कहा कि किसी गौ तस्कर की औकात नहीं है कि गाय को हाथ भी लगा दे. इसके अलावा उन्होंने विपक्ष और खासकर अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा.

केशव प्रसाद मौर्य का झुकाव शंकराचार्य के पक्ष में

जनवरी में माघ मेले में स्नान को लेकर हुए विवाद से अब तक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के हित में ही दिखाई दिए. उन्होंने अनशन पर जब बैठे तब भी निवेदन कर स्नान करने की अपील की थी. और आज वाराणसी दौरे पर भी उन्होंने उसी ओर संकेत दिया. जबकि शंकराचार्य लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा निशाना साध रहे हैं. पत्रकारों के सवालों पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लखनऊ में वे ह्यशंकराचार्य का स्वागत करेंगे'।

प्रधानमंत्री ने बहरीन के शाह के साथ टेलीफोन पर बातचीत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज बहरीन के शाह, महामहिम हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने बहरीन पर हाल ही में हुए हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने इस कठिन घड़ी में बहरीन की जनता के प्रति भारत की दृढ़ एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने बहरीन में रहने वाले भारतीय समुदाय को प्रदान किए गए निरंतर सहयोग और देखभाल के लिए महामहिम शाह का आभार भी व्यक्त किया।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपनी पोस्ट के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए लिखाः "बहरीन के शाह, महामहिम हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ सार्थक टेलीफोन वार्ता हुई।

भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए गए, दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया गया

(एजेंसी)।

भारत और कनाडा ने आज नई दिल्ली में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के लिए वार्ता शुरू की और इसे जल्द अंतिम रूप देने का निर्णय लिया। भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के संदर्भ की शर्तों (टीओआर) पर दो मार्च 2026 को भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री श्री मनिंदर सिद्धू ने हस्ताक्षर किए तथा नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री श्री मार्क कार्नी की उपस्थिति में इन दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया गया।

समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का उल्लेख किया कि द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता आर्थिक सहयोग की पूर्ण संभावनाओं को साकार करना है, जिसके लिए भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) को शीघ्र अंतिम रूप देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा कि यह एक मूल्यवान साझेदारी का विस्तार है, जिसमें नई महत्वाकांक्षा, स्पष्ट लक्ष्य और दूरदर्शिता शामिल साथ ही, यह दो आत्मविश्वासी देशों के बीच ऐसी साझेदारी है जो अपने भविष्य की दिशा स्वयं निर्धारित कर रहे हैं।

भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के लिए वाताओं की संदर्भ शर्तें (टीओआर) वार्ता की संरचना, आवृत्ति और कार्यप्रणाली निर्धारित करेंगी। ये संदर्भ शर्तें एक महत्वाकांक्षी, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) को संपन्न करने के उद्देश्य से वाताओं को सुगम बनाने हेतु मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगी।

अक्टूबर 2025 में कनाडा के कनानास्किस में आयोजित जी7 बैठक से इतर हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनो देशों के नेताओं द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुपालन में दोनों पक्षों ने भारत-कनाडा सीईपीए की बातचीत के लिए टीओआर को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया।

इन वाताओं में वस्तुओं, सेवाओं और पारस्परिक रूप से सहमति के अन्य नीतिगत क्षेत्रों में व्यापार शामिल होगा।

कनाडा 2025 तक 4.165 करोड़ लोगों का बाजार और पीपीपी के के आधार 2340 अरब अमेरिकी डॉलर का जीडीपी बाजार प्रस्तुत करता है।

सीईपीए में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने और विस्तारित करने की महत्वपूर्ण क्षमता है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 8.66 अरब अमेरिकी डॉलर (नियार्तः 4.22 अरब अमेरिकी डॉलर; आयातः 4.44 अरब अमेरिकी डॉलर) था। (स्रोतः डीजीसीआई एवं एस)

भारत से कनाडा को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स, लोहा और इस्पात, समुद्री भोजन, सूती वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक सामान और रसायन आदि शामिल हैं। भारत द्वारा कनाडा से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में दाल, मोती और अर्ध-कीमती पत्थर, कोयला, उर्वरक, कागज और कच्चा पेट्रोलियम शामिल हैं।

भारत द्वारा कनाडा को निर्यात की जाने वाली सेवाओं के प्रमुख क्षेत्रों में दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं और अन्य व्यावसायिक सेवाएं शामिल हैं। इन क्षेत्रों में भविष्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं और सीईपीए के संपन्न होने के बाद इनमें और विस्तार होने की उम्मीद है।

कनाडा में 425,000 से अधिक भारतीय छात्र और एक मजबूत भारतीय समुदाय भी रहता है।

आज से लेकर चार मार्च तक बंद रहेगा चिड़ियाघर, तीन मार्च तक इमामबाड़े पर लगे रहेंगे ताले

लखनऊ , (एजेंसी)। होली के मौके पर लखनऊ का चिड़ियाघर आज से लेकर चार मार्च तक पूरी तरह से बंद रहेगा। उधर खामनेई की मौत की वजह से इमामबाड़ा तीन मार्च तक बंद रहेगा।

नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान (चिड़ियाघर) होली पर्व पर तीन दिन बंद रहेगा। इस अवधि में दर्शक चिड़ियाघर नहीं घूम सकेंगे। चिड़ियाघर के निदेशक संजय कुमार बिस्वाल के अनुसार, सोमवार को चिड़ियाघर में सार्वजनिक अवकाश रहता है। जबकि, मंगलवार और बुधवार को होली पर्व पर छुट्टी की गई है। 5 मार्च को प्राणी उद्यान पूर्व की तरह खुलेगा।

तीन मार्च तक बंद रहेगी भूलभुलैया

ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या के विरोध में शिया समुदाय की ओर से तीन दिन तक शोक व प्रदर्शन का एलान किया गया है। एहतियात के तौर पर बड़ा इमामबाड़ा (भूलभुलैया) और छोटा इमामबाड़ा तीन मार्च तक पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। एडीएम (पूर्वी) महेंद्रपाल सिंह ने बताया कि खामनेई की हत्या के विरोध में शिया समुदाय के लोगों ने तीन दिन तक शोक और प्रदर्शन का एलान किया है। उनकी धार्मिक भावनाओं, शांति व पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि तीन मार्च के बाद दोनों इमामबाड़े पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की हत्या पर शिया समुदाय में आक्रोश को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में खेलो इंडिया और माय भारत के संयुक्त प्रयास से आयोजित होने वाली अनूठी राष्ट्रव्यापी अस्मिता लीग की घोषणा

खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में खेलो इंडिया और माय भारत के संयुक्त प्रयास से आयोजित होने वाली अनूठी राष्ट्रव्यापी अस्मिता लीग की घोषणा की

8 मार्च को, एसएआई और माय भारत के संयुक्त प्रयास से ये कार्यक्रम एक साथ 250 स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे, इनमें अंडर 13, 13-18 और 18+ आयु वर्ग के एथलीट भाग लेंगे

'इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच के अनुरूप गांवों और छोटे कस्बों की लड़कियों को खेल करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है'

(एजेंसी)।

खेल जगत में महिलाओं को सम्मानित करने की एक अनूठी पहल के तहत, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के अस्मिता (सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है और इसका उद्देश्य देश भर में महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना तथा उन्हें खेलने के लिए बढ़ावा देना है) कार्यक्रम के अंतर्गत 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 250 स्थानों पर एक विशाल राष्ट्रव्यापी एथलेटिक्स लीग का आयोजन किया जाएगा। राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खडसे ने आज यह घोषणा की।

श्रीमती खडसे ने दिल्ली के मेजर ध्यान चंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित एक मीडिया सम्मेलन में कहा "देश भर की हमारी युवा महिलाओं को एकीकृत करने का इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता और देश भर में लोकप्रियता हासिल कर रहे अस्मिता मंच का उपयोग करने से बेहतर साधन और क्या हो सकता है"।

अस्मिता, खेलो इंडिया के लैंगिक समानता के मिशन का हिस्सा है। इसका उद्देश्य लीग और प्रतियोगिताओं के माध्यम से महिलाओं में खेलों को बढ़ावा देना है। भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) राष्ट्रीय खेल संघों को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आयु वर्गों में खेलो इंडिया महिला लीग आयोजित करने में सहयोग करता है। 2021 में शुरू हुई अस्मिता लीग का उद्देश्य न केवल खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है।

अवकाश की सूचना

हमारे प्रिय पाठकों को सूचित किया जाता है कि होली पर्व के अवसर पर कार्यालय में 04 मार्च 2026 को अवकाश होने के कारण 05 मार्च का समाचार पत्र नहीं मिल सकेगा। अगला समाचार पत्र 06 मार्च, 2026 शुक्रवार के दिन प्राप्त हो सकेगा।

- सम्पादक

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

लखनऊ में किशोर की गोली मारकर हत्या, घर से बुलाकर ले गए थे दोस्त

(एजेंसी)।

लखनऊ। लखनऊ के कृष्णानगर में सोमवार शाम एक सनसनीखेज वारदात से इलाके को हिला दिया। यहां एक करीब 12 वर्षीय मासूम बच्चे उनैज खान के सिर में की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि पुरानी लड़ाई का बदला लेने के लिए हत्या की गई।

परिजनों के मुताबिक, उनैज ने रोजा रखा हुआ था। शाम को रोजा खोलने के बाद उसके दोस्त उसे घर से बुलाकर कार में बिठाकर ले गए थे, जिसके बाद उसका गोली लगा शव मिला है। परिजनों ने बताया कि उन्होंने बेटे से पूछा भी था कि कोई विवाद तो नहीं है, लेकिन कुछ बताया नहीं। बच्चे की हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ।

सरोजनीनगर के बेहसा निवासी उनैज खान (12) कृष्णानगर के बरिगवां में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारोपी कार से उसका शव लोकबंधू अस्पताल की इमरजेंसी में डालकर भाग गये।

भाजपा नेता के भतीजे समेत चार के खिलाफ तहरीर

घटना की जानकारी होने पर पहुंचे पिता जमीर खान ने कृष्णानगर थाने में भाजपा नेता व पूर्व एमएलसी अरविंद त्रिपाठी उर्फ गुड्डू त्रिपाठी के भतीजे समेत चार के खिलाफ नामजद तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लिया है।

वहीं, भाजपा नेता के परिजन के मुताबिक, सभी बच्चे जन्मदिन की पार्टी में शामिल हुए थे। इसी दौरान रील बनाते समय गोली लगने से उनैज की मौत हो गई। एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा के मुताबिक रिवाल्वर जब्त कर लिया है। मामले की हर बिंदु पर जांच कर रही है।

सरोजनीनगर के अमौसी स्थित बेहसा निवासी जमीर खान बिजली के उपकरण की दुकान चलाते हैं। जमीर के परिवार में दो बेटे उनैज व उमैज पत्नी शमा है।

जमीर ने बताया कि सोमवार दोपहर करीब 3.30 बजे कृणानगर सेक्टर-बी बरिगवां निवासी भाजपा नेता व पूर्व एमएलसी अरविंद त्रिपाठी उर्फ गुड्डू त्रिपाठी का भतीजा व अन्य चालक के साथ उनके घर पहुंचे। जहां उनैज को जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए साथ चलने को कहा।

उनैज ने रोजा खोलने की बात कहा। पर, चारों ने उसे जबरदस्ती साथ लेकर कृष्णानगर के बरिगवां पहुंचे। पूर्व एमएलसी के भाई व नवनीत के पिता संजीव त्रिपाठी के घर के पास पहुंचे। वहां कार में उनैज के माथे पर लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मार दी। उसकी मौत कार में ही हो गई थी। चारों कार से लोकबंधू अस्पताल पहुंचे। वहां उनैज को इमरजेंसी में दाखिल किया। इसके बाद चुपचाप वहां भाग गये।

चार घंटे पर पत्नी के मोबाइल पर दी गई सूचना

जमीर के मुताबिक, उनैज की मौत की सूचना उसके घर से निकलने के चार घंटे बाद दी गई। नवनीत के पिता संजीव त्रिपाठी ने जमीर की पत्नी शमां के मोबाइल पर कॉल कर सूचना दी। परिजन लोकबंधू पहुंचे जहां उसका शव पड़ा था।

परिजन के मुताबिक वहां संजीव त्रिपाठी के दर्जनों करीबी पहुंच गये थे। बेटे का शव देखने नहीं दिया।

मस्कट-रियाद और जेद्दा की तीन उड़ानें बहाल, लखनऊ में 90% तक घटा इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक

ईरान-इजरायल/अमेरिका संघर्ष के कारण लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अंतरराष्ट्रीय वायु यातायात में 90% की भारी गिरावट आई है।

ईरान-इजरायल संघर्ष से लखनऊ एयरपोर्ट पर यातायात 90% घटा।

खाड़ी देशों की कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द, यात्री संख्या गिरी।

मस्कट, रियाद, जेद्दा की कुछ उड़ानें सोमवार को बहाल हुईं।

लखनऊ। ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के बीच चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल वायु यातायात 90 प्रतिशत तक कम हो गया है। लखनऊ एयरपोर्ट से खाड़ी देशों को जाने वाली उड़ानें निरस्त कर दी गई हैं। इसके चलते आवाजाही की 18 से 20 इंटरनेशनल उड़ानों की संख्या घटकर दो तक पहुंच गई है।

हालांकि, सोमवार को एविएशन सेक्टर ने थोड़ी सी राहत ली। लखनऊ से जेद्दा, रियाद और मस्कट जाने वाली चार उड़ानें सोमवार को रवाना हुईं। हालांकि यह उड़ानें सलाम एयर, फ्लाईनस व फ्लाई दुबई की रहीं। इसमें भारतीय एयरलाइन ने अभी अपनी उड़ानें नहीं शुरू की हैं। सोमवार को ओमान की उड़ान से मात्र 21 और सलाम एयर की उड़ान से 75 यात्री रवाना हो सके।

विज्ञापना हटाएं
सिर्फ खबर पढ़ें
छअळएरळ

अवैध हथियारों के साथ राजस्थान में पंजाब के दो युवक गिरफ्तार

एनकाउंटर में ढेर... धार्मिक मिजाज का था मदरसा में तालीम लेने खामेनेई की मौत के बाद लखनऊ में शिया समुदाय ने बड़े पैमाने पर

ईरान-इजरायल युद्ध से गाजियाबाद के उद्योगों पर संकट, निर्यात

पीएम मोदी ने यूएई हमलों की निंदा की, भारतीय समुदाय की सुरक्ष

चंडीगढ़ में टीबी का बढ़ता खतराः हर दिन 18 नए मरीज, स्वास्थ्य

ईरान-इजरायल युद्ध का दिखेगा असर, ड्राई फ्रूट के रेट बढ़ेंगे,

ओडिशा में नक्सलवाद को करारा झटका, बरगढ़-बलांगीर आधिकारिक रूप

यूट्यूबर सलीम पर हमला करने वाला एक लाख का इनामी जीशान एनकाउं

आगरा में गुप्ता बैट्री हाउस के

नीति आयोग और जेआईसीए ने महत्वाकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में जापान-भारत सहयोगात्मक कार्यों के द्वितीय चरण के लिए चर्चा के अभिलेख पर हस्ताक्षर किए

(एजेंसी)।

भारत-जापान विकास सहयोग को मजबूत करने की दिशा में नीति आयोग और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, आज "सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में जापान-भारत सहकारी कार्यों के कार्यक्रम को बढ़ावा देने की परियोजना - चरण क्क" के लिए चर्चा अभिलेख (आरओडी) पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक, आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम के श्री रोहित कुमार और जेआईसीए भारत के मुख्य प्रतिनिधि ताकेउची ताकुरो की उपस्थिति रहे।

यह सहयोग भारत-जापान की मजबूत विकास साझेदारी की पुष्टि करता है और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में विशेष रूप से आकांक्षी जिलों (एडी) और आकांक्षी ब्लॉकों (एबी) में संयुक्त प्रयासों को आगे बढ़ाता है। श्री रोहित कुमार ने कहा कि इस साझेदारी में संस्थागत शक्तियां, साझा ज्ञान और जमीनी अनुभव एक साथ है और इसका उद्देश्य वंचित क्षेत्रों में समावेशी विकास को गति देना है।

एडीपी और एबीपी के अंतर्गत इस परियोजना का उद्देश्य वैश्विक भागीदारी, स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास तथा बुनियादी ढांचा - इन छह विषयों में नीतिगत ढांचों और कार्यान्वयन प्रणालियों को सुदृढ़ करना है। यह परियोजना संस्थागत क्षमता निर्माण, बेहतर निगरानी एवं मूल्यांकन तथा सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी स्थानीयकरण पर केंद्रित है।

इस परियोजना के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियों में लोगों के बीच आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण सम्बंधी कार्य, जापान-भारत ज्ञान मंच, सर्वोत्तम तौर-तरीकों की पहचान और प्रसार तथा आकांक्षी जिलों और आकांक्षी ब्लॉकों को लक्षित सहायता प्रदान करना शामिल है।

जेआईसीए इंडिया के मुख्य प्रतिनिधि श्री ताकेउची ताकुरो ने एडीपी और एबीपी के सफल कार्यान्वयन की सराहना करते हुए कहा कि भारत की जिला और ब्लॉक-स्तरीय निगरानी प्रणालियां वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जापान-भारत साझेदारी को और मजबूत करने वाली यह परियोजना पारस्परिक रूप से लाभकारी और सहयोगात्मक पहल है।

नीति आयोग ने राज्य सहायता मिशन के अंतर्गत प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया

(एजेंसी)।

नीति आयोग ने अपने राज्य सहायता मिशन (एसएसएम) के तहत प्राकृतिक खेती पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें देश भर से किसानों, नीति निमार्ताओं, वैज्ञानिकों, स्टार्टअप और नागरिकों ने एक साथ भाग लिया।

इस कार्यशाला के दौरान प्राकृतिक खेती पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रशिक्षण नियमावली की शुरूआत की गई, जिसका उद्देश्य किसानों, विस्तार अधिकारियों और जमीनी स्तर के कार्यकताओं को प्राकृतिक खेती पद्धतियों पर क्षेत्र-प्रासंगिक और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना है।

गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत ने इस कार्यशाला को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने टिकाऊ, किसान-केंद्रित कृषि प्रणालियों के महत्व और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, इनपुट लागत को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने में प्राकृतिक खेती की भूमिका पर जोर दिया।

इस कार्यक्रम में जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय, डॉ. वाईएस परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय और गुजरात प्राकृतिक कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय सहित प्रमुख शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों की सक्रिय भागीदारी रही।

पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और ओडिशा के किसानों, कृषि अधिकारियों और कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) के वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक खेती पर विचार-विमर्श किया।

एपीडा, नाबार्ड, सहकारिता मंत्रालय, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन विभाग (डीएएचडी), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान सहित प्रमुख केंद्रीय संस्थानों और मंत्रालयों के अधिकारियों ने भी कार्यशाला में भाग लिया और अभिसरण, प्रमाणीकरण, बाजार संबंधों और संस्थागत समर्थन पर अपने विचार साझा किए।

इस कार्यशाला में कृषि क्षेत्र के स्टार्टअप, नागरिकों, अग्रणी किसानों और किसान उत्पादक समूहों ने देश में प्राकृतिक खेती को समर्थन देने वाले बढ़ते इको-सिस्टम पर बल दिया।

कार्यशाला में पहले दिन आयोजित खुली चर्चा में कुल 770 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें किसानों और विशेषज्ञों को प्राकृतिक खेती को अपनाने, प्रमाणीकरण, बाजार और संस्थागत समर्थन से संबंधित अपनी समस्याओं, जमीनी स्तर की चुनौतियों और आशंकाओं पर खुलकर चर्चा करने का अवसर मिला। इस चर्चा में किसान नेतृत्व मॉडलों की आवश्यकता पर आम सहमति बनी।

कार्यशाला के दूसरे दिन प्रतिभागियों को जमीनी स्तर पर प्राकृतिक कृषि पद्धतियों का अवलोकन करने और विशेषज्ञों से बातचीत करने का अवसर मिला। इस दौरान विभिन्न विदेशी फसलों के लिए

भारतीय वैज्ञानिकों ने 50 साल पुराने जैविक नियम के पुनर्लेखन में सहायता की

(एजेंसी)।

एक नए अध्ययन की सहायता से जीवाणु जीन विनियमन के प्रमुख पाठ्यपुस्तक मॉडल से अलग हटकर जीवाणु जीन विनियमन और इसके विकास को समझने के लिए नए रास्ते उजागर किए हैं।

इससे संक्रमण तंत्र को अवरुद्ध करने वाले बेहतर एंटीबायोटिक्स या नियामक अवरोधकों की रूपरेखा तैयार करने में सहायता मिल सकती है। जो कुशलतापूर्वक जैव ईंधन, जैव अपघटनीय प्लास्टिक या चिकित्सीय यौगिकों का उत्पादन करने वाले सूक्ष्मजीवों को तैयार करने में मददगार हो सकता है।

लगभग 50 वर्षों से, जीवविज्ञान यह बताता आ रहा है कि जीवाणु तथाकथित "σ (सिग्मा) चक्र" की सहायता से अपने जीन को कैसे सक्रिय करते हैं - ये ऐसे कारक हैं जो आरएनए पॉलीमरेज से जुड़कर प्रतिलेखन की शुरूआत करते हैं और फिर अलग होकर जीन के विस्तार की अनुमति देते हैं। यह अवधारणा मुख्य रूप से जीवाणु उपभेद ई. कोलाई σ70 के अवलोकनों पर आधारित है।

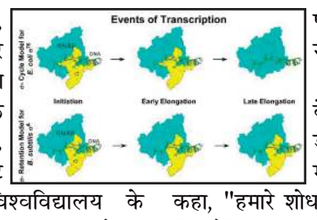

हालांकि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के एक स्वायत्त संस्थान, बोस इंस्टीट्यूट और रटगर्स विश्वविद्यालय के शोधकताओं ने खुलासा किया है कि यह चक्र एक सार्वभौमिक घटना नहीं है।

नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज (पीएनएएस) की कार्यवाही में प्रकाशित एक अध्ययन में उन्होंने बताया है कि दशकों से चली आ रही वैज्ञानिक मान्यता के विपरीत, बैसिलस सबटिलिस में प्रमुख प्रतिलेखन आरंभिक कारक - σअ - और एस्चेरिचिया कोलाई σ70 कारक का एक संशोधित संस्करण, आरंभिक प्रक्रिया के बाद मुक्त होने के बजाय, प्रतिलेखन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज से बंधे रहते हैं।

बोस इंस्टीट्यूट के प्रमुख लेखक डॉ. जयंता मुखोपाध्याय ने कहा, "हमारे शोध से पता चलता है कि बैसिलस सबटिलिस में , σअ कारक ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया के दौरान आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ा रहता है। इससे बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और जीन विनियमन के बारे में हमारी सोच में मौलिक परिवर्तन आता है।"

जैव रासायनिक परीक्षण, क्रोमेटिन इम्यूनोप्रिसिपिटेशन और फ्लोरेसेंस-आधारित इमेजिंग जैसी आधुनिक तकनीकों के संयोजन का उपयोग करते हुए, शोधकताओं ने सिग्मा कारक के व्यवहार का वास्तविक समय में अवलोकन किया। उन्होंने पाया कि बैसिलस सबटिलिस σअ और ई. कोलाई σ70 का एक प्रकार जिसमें 1.1 नामक भाग की कमी है, प्रतिलेखन परिसरों के साथ स्थिर रूप से जुड़े रहते हैं। यह पूर्ण-लंबाई वाले ई. कोलाई σ70 के बिल्कुल विपरीत है, जो विस्तार के दौरान अनियमित रूप से मुक्त हो जाता है।

बोस इंस्टीट्यूट के सह-लेखक अनिरुद्ध तिवारी ने कहा, "ये निष्कर्ष इस बात का पुख्ता सबूत देते हैं कि लंबे समय से स्वीकृत σ चक्र सभी बैक्टीरिया पर लागू नहीं होता है। इससे बैक्टीरिया के जीन नियमन और उसके विकास को समझने के नए रास्ते खुलते हैं।"

21वीं केंद्रीय निगरानी समिति ने प्रदूषित नदी क्षेत्रों और सीवेज प्रबंधन पर राज्यवार प्रगति की समीक्षा की

डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर के सचिव ने समयबद्ध कार्रवाई अपनाने और एसटीपी के प्रदर्शन और निगरानी को मजबूत करने का आग्रह किया

(एजेंसी)।

नदी पुनर्जीवन संबंधी केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) की 21वीं बैठक आज जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनर्जीवन विभाग के सचिव श्री वीएल कंथा राव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री राजीव कुमार मित्तल सहित वरिष्ठ अधिकारियों, एनएमसीजी के अन्य अधिकारियों और राज्य सरकारों तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

समिति ने सीपीसीबी की 2025 की रिपोर्ट के आधार पर प्रदूषित नदी क्षेत्रों की नवीनतम स्थिति की समीक्षा की और स्वीकृत कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्यों द्वारा की गई प्रगति का आकलन किया। अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि नदी के जल की गुणवत्ता में सतत सुधार न केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण पर बल्कि उसके प्रभावी उपयोग, नियामक अनुपालन और समय पर परियोजना निष्पादन पर भी निर्भर करता है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सीवेज उपचार की कमियों को दूर करना, मौजूदा सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) के प्रदर्शन में सुधार करना, चल रही और निविदाकृत एसटीपी परियोजनाओं और सीवेज नेटवर्क के विकास से संबंधित कार्यों में तेजी लाना, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण को मजबूत करना, उपचारित अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग को बढ़ाना और बाढ़ के मैदानों के सीमांकन में तेजी लाना शामिल थे। सचिव ने राज्यों को प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम करने का भी निर्देश दिया।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026: ऐतिहासिक वैश्विक घोषणापत्र और एआई में निवेश के लिए प्रमुख प्रतिबद्धताएं

(एजेंसी)।

16 से 21 फरवरी 2026 तक आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ने वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में अपनी पहचान बनाई। इस शिखर सम्मेलन में व्यापक भागीदारी देखी गई, जिसमें लगभग 6 लाख प्रतिभागियों ने व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लिया जबकि लाइव वर्चुअल स्ट्रीमिंग के माध्यम से 9 लाख से अधिक लोगों ने इसे देखा। 100 से अधिक देशों और 20 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों ने इस आयोजन में भाग लिया।

शिखर सम्मेलन के दौरान, भारत ने 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026' में "24 घंटों में एआई जिम्मेदारी अभियान के लिए सबसे अधिक प्रतिज्ञाएं प्राप्त करने" का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का खिताब सफलतापूर्वक हासिल कर किया जिसमें 2.5 लाख से अधिक 'एआई जिम्मेदारी प्रतिज्ञाएं' प्राप्त हुईं। शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण घोषणा भारत की संप्रभु कंप्यूटिंग क्षमता के विस्तार से संबंधित थी। इंडियाएआई मिशन के तहत पहले से ही उपलब्ध कराए गए 38,000 से अधिक जीपीयू के अलावा, आने वाले हफ्तों में 20,000 अतिरिक्त जीपीयू जोड़े जाएंगे, जिससे राष्ट्रीय एआई बुनियादी ढांचे को और मजबूती मिलेगी।

वैश्विक घोषणाएं और रणनीतिक एआई साझेदारियां

इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर जिम्मेदार, सुदृढ़ और समावेशी एआई अपनाने के लिए रूपरेखाओं को आगे बढ़ाना था।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट घोषणापत्र को 92 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन दिया। यह घोषणापत्र शिखर सम्मेलन के दौरान सात विषयगत कार्य समूहों द्वारा किए गए कार्यों को मान्यता देता है।

नई दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट कमिटमेंट्स की घोषणा 13 प्रमुख वैश्विक और भारतीय फ्रंटियर मॉडल डेवलपर्स द्वारा विश्वसनीय और समावेशी एआई को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

स्वैच्छिक पहल के अंतर्गत ग्लोबल एआई इम्पैक्ट कॉमन्स का शुभारंभ हुआ जिसमें 30 से अधिक देशों की 80 से अधिक प्रभावकारी कहानियां शामिल हैं, जो देशों को आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए सफल एआई उपयोग के मामलों को साझा करने, दोहराने और विस्तारित करने में सक्षम बनाती है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से इक्विटेबल एआई ट्रांजिशन प्लेबुक का विमोचन किया गया है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों को एआई-संचालित उभरते अवसरों के लिए तैयार करना है।

लचीली, नवोन्मेषी और कुशल एआई के लिए स्वैच्छिक मार्गदर्शक सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिन्हें 20 से अधिक देशों ने समर्थन दिया है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में कौशल विकास के लिए स्वैच्छिक मार्गदर्शक सिद्धांतों पर 23 देशों ने हस्ताक्षर किए।

22 देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा समर्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोकतांत्रिक प्रसार के लिए चार्टर को अपनाया गया।

यूनेस्को और फ्रांस के साथ साझेदारी में रेजिलिएंट एआई चैलेंज का शुभारंभ।

सुदृढ़ एआई अवसंरचना को आगे बढ़ाने के लिए प्लेबुक का विमोचन।

औपचारिक शुभारंभ से पहले 22 भागीदार देशों के साथ ट्रस्टेड एआई कॉमन्स की घोषणा की गई।

22 देशों द्वारा अनुमोदित एआई गवर्नेंस पर मार्गदर्शन नोट्स जारी किए गए।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशन को बढ़ावा देने के लिए गठबंधन की घोषणा, जिसे 20 देशों और यूनिसेफ का समर्थन प्राप्त है।

विज्ञान संस्थानों के लिए एआई नेटवर्क का शुभारंभ, जिसमें शुरूआत में 19 भागीदार देश शामिल हैं।

एआई इम्पैक्ट एक्सपो, नॉलेज आउटपुट और जमीनी स्तर पर स्वीकार्यता

एआई इम्पैक्ट एक्सपो विश्व स्तर पर सबसे बड़ी एआई प्रदर्शनियों में से एक के रूप में उभरी, जिसमें 10 विषयगत मंडपों में 850 से अधिक प्रदर्शक शामिल थे।

नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में, एक ओपन-सोर्स हैंडहेल्ड सहायक उपकरण का लाइव प्रदर्शन किया गया, जो आवाज के आधार पर वस्तुओं और परिवेशों को पहचानने और कई भाषाओं में जवाब देने में सक्षम है। भाषिनी और करंट एआई द्वारा विकसित इस प्रोटोटाइप को आगे तकनीकी सुधार और उपयोग के मामलों के विकास के लिए स्टार्टअप जगत के लिए खोल दिया गया।

उच्च प्रभाव वाले एआई परिनियोजनों का दस्तावेजीकरण करने वाली छह वैश्विक केसबुक जारी की गईं जो इस प्रकार से हैं:

आईटीआई प्रशिक्षण में बड़ा सुधार: 150 घंटे का अनिवार्य ओजेटी/ग्रुप प्रोजेक्ट प्रावधान लागू

(एजेंसी)।

भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने आईटीआई ट्रेनीज के लिए नए नियम जारी किए हैं। अब औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के छात्रों को क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम (सीटीएस) के तहत 150 घंटे की अनिवार्य ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) या ग्रुप प्रोजेक्ट करना होगा। यह नियम शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू है।

पुराने ट्रेनिंग सिस्टम में यह देखा गया है कि ट्रेनीज ज्यादातर आईटीआई कैंपस में मौजूद पुराने टूल्स और मशीनों से ही ट्रेनिंग लेते हैं। इससे उन्हें मॉडर्न और नई इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का सीधा अनुभव कम मिल पाता है। इसी कारण जब उनकी इंडस्ट्री में नौकरी लगती है, तो कई ट्रेनीज को फिर से ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) की जरूरत पड़ती है। तेजी से बदल रहे इन्डस्ट्रीज और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को देखते हुए, इंडस्ट्री-इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग को मजबूत बनाना जरूरी हो गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी) 2020 के अनुसार, डीजीटी ने सीटीएस की योग्यता में बदलाव किया है। अब सालाना ट्रेनिंग का समय 1600 घंटे से घटाकर 1200 घंटे कर दिया गया है। इसके साथ ही 150 घंटे की अनिवार्य ओजेटी या ग्रुप प्रोजेक्ट जोड़ा गया है, ताकि ट्रेनीज को असली इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट का अनुभव मिल सके।

इस अवसर पर भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयन्त चौधरी ने कहा कि 'आईटीआई छात्रों के लिए 150 घंटे की अनिवार्य स्ट्रक्चर्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग (ओजटी) या ग्रुप प्रोजेक्ट एक बड़ा सुधार है। इससे वोकेशनल एजुकेशन की क्वालिटी और उपयोगिता बढ़ेगी। तेजी से बदल रही इंडस्ट्रियल दुनिया में सिर्फ क्लासरूम लर्निंग काफी नहीं है। असली वर्कप्लेस एक्सपोजर से छात्रों में प्रैक्टिकल स्किल, कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनलिज्म बढ़ता है। यह कदम इंडस्ट्री और ट्रेनिंग संस्थानों के बीच लिंकेज को मजबूत करेगा और युवाओं को सच में जॉब-रेडी और फ्यूचर-रेडी बनाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि 'सरकार का मकसद सिर्फ सर्टिफिकेट देना नहीं है, बल्कि युवाओं को ऐसी स्किल्स देना है जो असली इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार हों। इंडस्ट्री-इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग मॉडल के जरिए यह कदम 'कुशल भारत -विकसित भारत' के विजन को तेजी से आगे बढ़ाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी) 2020 के अनुसार, यह पहल स्किल ट्रेनिंग को ज्यादा प्रैक्टिकल, उपयोगी और इंडस्ट्री-फोकस्ड बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी'।

ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) / ग्रुप प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद आईटीआई ट्रेनीज की एम्प्लॉयबिलिटी को मजबूत करना है, ताकि वे इंडस्ट्री की असली जरूरतों के अनुसार स्किल्ड बन सकें। इसके जरिए इंडस्ट्री और आईटीआई के बीच सहयोग बढ़ेगा। इससे ट्रेनिंग प्रोग्राम को इंडस्ट्री की मौजूदा जरूरतों के हिसाब से अपडेट रखा जा सकेगा। यह पहल ट्रेनीज को वर्कफोर्स में आसानी से शामिल होने में मदद करेगी। इससे उन्हें नौकरी पाने और वर्कप्लेस एनवायरनमेंट में तालमेल बैठाने में आसानी होगी। साथ ही, असली इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में उनकी स्किल्स का लगातार इवैल्यूएशन होगा, ताकि उनकी दक्षता इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अनुसार विकसित हो सके।

इस नियम के तहत हर ट्रेनी के लिए ओजेटी या, जहाँ संभव न हो, संबंधित ट्रेड पर आधारित प्रोजेक्ट करना अनिवार्य है। ट्रेनी केवल तभी ओजेटी/प्रोजेक्ट के लिए पात्र होंगे जब उन्होंने आईटीआई में प्रवेश के बाद कम से कम तीन महीने का ट्रेनिंग पूरा कर लिया हो। ट्रेनिंग इंडस्ट्री मेंटर के मार्गदर्शन में होगी और उनके प्रदर्शन का नियमित मूल्यांकन किया जाएगा। ट्रेनीज को अपनी गतिविधियाँ और अर्जित स्किल्स लॉगबुक में रिकॉर्ड करनी होंगी। अंतिम मूल्यांकन प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान मेंटर/ट्रेनर के मूल्यांकन, लॉगबुक की समीक्षा और मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा और ग्रेड अंकपत्र में दिखाया जाएगा। सफलतापूर्वक पूरा करने पर आईटीआई द्वारा इंडस्ट्री-अप्रूव्ड सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ट्रेनीज की सुरक्षा के लिए राज्य निदेशालय आकस्मिक ग्रुप बीमा जैसी व्यवस्थाएँ कर सकते हैं। दूर-दराज जगहों पर ओजेटी करने वाले ट्रेनीज के लिए यात्रा और आवास) की सुविधा भी दी जा सकती है। भविष्य में ओजेटी को डेटा-ड्रिवन ग्रेडिंग मेथडोलॉजी (डीडीजीएल) में एक महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में शामिल किया जाएगा। ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग (डीएसटी) में पढ़ रहे ट्रेनीज के लिए ओजेटी के बजाय अनिवार्य प्रोजेक्ट कार्य रखा गया है, क्योंकि वे पहले से ही इंडस्ट्री ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके होते हैं।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

गहरे अंधकार में ईरानी भविष्य

नोबेल पीस प्राइज के दावेदार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसके परंपरागत एवं चिरपरिचित शत्रु इजरायल के साथ मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई सहित प्राथम एवं द्वितीय पंक्ति के नेतृत्व का सफाया कर दिया और लगभग 40 सैन्य कमांडरों को मार डाला। राजनीतिक नेतृत्व विहीन और सैन्य मार्गदर्शक नेतृत्व के अभाव में अब ईरान अपने पड़ोसी मध्यपूर्व के देशों पर हमले कर रहा है। वह इजरायल के तेल अवीव पर भी लगातार हमले कर रहा है। ईरान में घुसे सीआईए और मोसाद ने पहले ही जमीनी तैयारी इस तरह कर ली थी कि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व और सैन्य कमांडरों के हर मूवमेंट की जानकारी उन्हें हासिल हो जाती थी और उसी के अनुसार वे अपनी रणनीति के मुताबिक ईरानी राजनीतिक एवं सेना अधिकारियों को निशाना बनाते रहे।

यह सच है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्राधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जिन तीन लक्ष्यों यानि परमाणु हथियार एवं सामग्री और बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को नष्ट करना तथा नेतृत्व परिवर्तन करने के लिए तेहरान पर हमले किए उन्हें प्राप्त करने में अब कोई संदेह नहीं लग रहा है। ईरान पर इस बार अमेरिका और इजरायल ने पूरी तैयारी से हमला किया है। शीर्ष राजनीतिक एवं सैन्य नेतृत्व का सफाया हो जाने के कारण सेना के स्थानीय अधिकारी खुद ही पैसले ले रहे हैं और यह मानकर चल रहे हैं कि अब उनके पास जब वुछ खोने को है ही नहीं तो क्यों न उन पड़ोसी मुल्कों को सबक सिखाए जो किसी न किसी रूप में अमेरिका के हितों के लिए साधन बने हुए हैं।

यह सच है कि ईरान में तमाम राजनेता भी हैं जो असंतुष्ट हैं और अपने बयानों के कारण वे जेल में बंद हैं। यदि अमेरिका उन राजनीतिक वैदियों को छुड़ा देता है तब तो यह माना जा सकता है कि अमेरिका और इजरायल जल्दी से जल्दी कोई वैकल्पिक सरकार बनाना चाहते हैं। ईरान के पूर्व शासक रजा पहलवी के अलावा भी अमेरिका और इजरायल के पास विकल्प होंगे, यही कारण है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने आम जनता को सलाह दी कि वे सामने आकर अपनी सरकार बना लें।

इतना तो निर्विवाद है कि अमेरिका ने हमले करके किसी भी देश पुनर्निमाण की जरूरत नहीं समझा है। इसलिए आज जिस तरह से ईरान में विध्वंस का बारूदी खेल चल रहा है, उसने इस देश को सैकड़ों साल पीछे धकेल दिया है। सीआईए और मोसाद ने न सिर्प ईरानी इंटेलीजेंस ब्यूरो कार्य प्राव्रिया को प्राभावित कर दिया है, वहीं बहुत सारे ईरानी इंटेलीजेंस के प्रातिनिधियों को खरीद लिया है। ईरानी इंटेलीजेंस ब्यूरो के एजेंटों ने ही शीर्ष नेताओं और सैन्य कमांडरों की सूचना अमेरिका और इजरायल के खुफिया प्रातिष्ठानों को दी है। बहरहाल ईरान में यदि कोई राजनीतिक सत्ता होती तो उसमें इतनी बौखलाहट न होती कि वह अपने सारे पड़ोसियों को अपने हमलों की वजह से अपना दुश्मन बनाता।

लब्बोलुआब यह है कि अमेरिका और इजरायल अब ईरान में उसके परमाणु संयंत्रों एवं सामग्री को समेटने की तैयारी में हैं साथ ही ईरान के बैलेस्टिक मिसाइल सिस्टम को तबाह करने की तरफ भी बढ़ चुके हैं। अब यदि अमेरिका ने एक बार फिर इराक, लीबिया और सीरिया की तरह ही ईरान को भी बर्बाद करके छोड़ना है और उसके पुनर्निर्माण की कोई नीति या कार्य योजना नहीं है तो ईरान के बौखलाए सैनिक इजरायल और अपने पड़ोसियों पर छिटपुट हमले करते रहेंगे और मध्यपूर्व में तनाव की आग धधकती रहेगी साथ ही पामि एशिया में भी अशांति रहेगी, जिससे सारे मुस्लिम देश प्राभावित होंगे और आए दिन अराजकता के शिकार ईरान में गृहयुद्ध की स्थिति देखने को मिल सकती है।

वुछ रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ईरान की मदद रूस और चीन करेंगे ताकि यह युद्ध काफी दिन चल सके। किन्तु लगता नहीं कि रूस और चीन इस युद्ध में वूदेंगे। रूस तो बिल्वुल सोच ही नहीं सकता क्योंकि ईरान की मदद करके न तो वह अपने देश के यहूदियों को नाराज करेगा और न ही सऊदी अरब, यूएई और ओमान जैसे मित्र देशों को।

श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में आयोजित स्टडी इन इंडिया एजुकेशन-डिप्लोमैटिक कॉन्क्लेव 2026 में 50 से अधिक देशों के राजनयिकों को संबोधित किया

शिक्षा मंत्री ने विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों से भारत की तेजी से विकसित हो रही नवाचार-संचालित शिक्षा प्रणाली के साथ सहयोग करने का आह्वान किया

सम्मेलन ने वैश्विक शैक्षणिक साझेदारी और राजनयिक मिशनों के साथ जुड़ाव को मजबूत किया

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से वैश्विक शिक्षा के क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत हुई है

भारत विश्व को अध्ययन करने, नवाचार और साथ मिलकर विकास करने के लिए आमंत्रित करता है

(एजेंसी)।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित 'स्टडी इन इंडिया एजुकेशन-डिप्लोमैटिक कॉन्क्लेव 2026' को संबोधित किया। इस सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के राजदूत, उच्चायुक्त, राजनयिक मिशनों के प्रतिनिधि और मंत्रालय के अधिकारियों ने उच्च शिक्षा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर विचार-विमर्श किया।

श्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत भारत की शिक्षा प्रणाली में हुए बदलाव का उल्लेख किया और कहा कि भारत शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण में हो रही महत्वपूर्ण प्रगति और गुणवत्ता, नवाचार तथा सामर्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक होगी। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में सीखने, अनुसंधान, नवाचार और उसे लागू करने के अपार अवसर प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका जीवंत ज्ञान तंत्र, जनसांख्यिकीय लाभांश और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। श्री प्रधान ने कहा कि भारत नई शिक्षा नीति 2020 और 'स्टडी इन इंडिया' पहल के माध्यम से छात्रों, शोधकताओं और संस्थानों के लिए वैश्विक अवसरों का विस्तार कर रहा है।

उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर से

लेकर सतत ऊर्जा तक, भारत एक विश्वसनीय नवाचार भागीदार के रूप में उभर रहा है और सहयोग, क्षमता निर्माण तथा साझा ज्ञान पर आधारित वैश्विक दक्षिण मॉडल को आगे बढ़ा रहा है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अनिश्चितता और तेजी से बदल रहे वैश्विक परिदृश्य में शिक्षा ही समाजों के बीच सबसे मजबूत सेतु है और भारत सहयोगी देशों के साथ ज्ञान के मजबूत सेतु बनाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने राजनयिकों से भारत की तेजी से विकसित हो रही, नवाचार-प्रेरित, बहुविषयक और सुलभ शिक्षा प्रणाली के साथ सहयोग करने का आह्वान किया।

उच्च शिक्षा सचिव डॉ. विनीत जोशी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पिछले छह वर्षों में भारत के उच्च शिक्षा सुधारों, विशेष रूप से बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा देने, कौशल विकास को शिक्षा के साथ एकीकृत करने और अंतर्राष्ट्रीयकरण को मजबूत करने के संदर्भ में स्पष्ट दिशा प्रदान की है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीय संस्थान संयुक्त, द्विभाषी और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वैश्विक जुड़ाव को गहरा कर रहे हैं, जबकि प्रमुख विश्वविद्यालय अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति का विस्तार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक पारदर्शी और समयबद्ध नियामक ढांचा तैयार किया है, जिससे विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने में सुविधा हो रही है, और ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के प्रमुख संस्थानों के आवेदनों को एक महीने के भीतर मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि 'स्टडी इन इंडिया' पहल भारत के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी वैश्विक शिक्षा साझेदारी का खुला निमंत्रण है।

इस सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर केंद्रित सत्र आयोजित किए गए:

भारतीय ज्ञान प्रणाली एक वैश्विक शैक्षणिक पेशकश के रूप में

एसपीएआरसी और जीआईएएन के माध्यम से अकादमिक साझेदारी

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उन्नत प्रौद्योगिकियां

भारत में विदेशी विश्वविद्यालय परिसरों के लिए यूजीसी विनियम 2023

अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर और सहायक ढांचे

भारत की कौशल संरचना का अंतर्राष्ट्रीयकरण

भारत इनोवेट्स 2026

सम्मेलन के दौरान भारत के विकसित हो रहे उच्च शिक्षा तंत्र पर प्रकाश डाला गया जिनमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग छात्र गतिशीलता, संयुक्त कार्यक्रम, अनुसंधान साझेदारी और परिसरों की स्थापना शामिल हैं।

स्टडी इन इंडिया एजुकेशन-डिप्लोमैटिक कॉन्क्लेव 2026 में शिक्षा के क्षेत्र में राजनयिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए भागीदार देशों के छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा और अल्पकालिक कार्यक्रमों में भाग लेने, संस्थागत सहयोग को प्रोत्साहित करने और विश्व स्तरीय दर्जा प्राप्त विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया गया।

एमईआईटीवाई ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए 30 किलोवाट केडब्ल्यू वाइड बैंड गैप (डब्ल्यूबीसी)- आधारित एकीकृत संचालन प्रणाली की शुरूआत की

(एजेंसी)।

इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए देश में बना 30 केडब्ल्यू वाइड बैंड गैप (डब्ल्यूबीजी) पर आधारित एकीकृत संचालन प्रणाली (आईडीएस) का आज चेन्नई में शुभारंभ किया गया। इस टेक्नोलॉजी को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक), तिरुवनंतपुरम ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास और लुकास टीवीएस के साथ मिलकर नेशनल मिशन ऑन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (एनएएमपीईटी) के तहत तैयार किया है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के सेक्रेटरी श्री एस. कृष्णन ने आईआईटी मद्रास में इसका शुभारंभ किया।

यह लॉन्च एडवांस्ड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने के एमईआईटीवाई के मिशन में योगदान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 30-केडब्ल्यू पावर क्लास भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक यात्री वाहन खंड के लिए खास तौर पर काम की है, जिसमें कॉम्पैक्ट कारें और फ्लीट मोबिलिटी प्लेटफॉर्म शामिल हैं। अभी, हाई-परफॉर्मेंस ईवी पावरट्रेन सिस्टम और जरूरी सेमीकंडक्टर-बेस्ड ड्राइव

कंपोनेंट का एक बड़ा हिस्सा आयात किया जाता है। ऐसे एकीकृत प्रणाली के स्वदेश में विकसित होने से आयात पर निर्भरता कम होगी, स्थानीयकरण के जरिए सिस्टम की लागत कम होगी, और प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना जैसी राष्ट्रीय पहलों के साथ स्केलेबल निर्माण में सहयोग मिलेगा।

इस टेक्नोलॉजी को लुकास टीवीएस के साथ मिलकर सफलतापूर्वक डिजाइन, फैब्रिकेट और वैलिडेट किया गया है और अब यह व्यावसायीकरण और बड़े पैमाने पर तैनाती के लिए तैयार है। इस एकीकृत संचालन टेक्नोलॉजी को सफलतापूर्वक अपनाने से भारत की ईवी आपूर्ति श्रृंखला काफी मजबूत हो सकती है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, थर्मल सिस्टम और कंट्रोल हार्डवेयर में एमएसएमई के लिए मौके बन सकते हैं, और सेमीकंडक्टर-आधारित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सॉल्यूशंस में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ सकती है। एनएएमपीईटी के जरिए, एमईआईटीवाई अगली पीढ़ी की मोबिलिटी और ऊर्जा प्रणाली के लिए दुनिया भर में प्रतिस्पर्धात्मक और आत्मनिर्भर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी बनाने के लिए नवोन्मेषन से चलने वाली साझेदारी को बढ़ावा दे रहा है।

सभा को संबोधित करते हुए, श्री एस. कृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' की कल्पना अत्याधुनिक विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के स्वदेशी विकास से पूरा हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आरऔरडी संस्थानों, शैक्षणिक समुदाय और उद्योग के बीच मिलकर किए गए नवोन्मेष से भारत के टेक्नोलॉजी आयात करने वाले देश से टेक्नोलॉजी विकसित करने वाले और निर्यात करने वाले देश में बदलाव को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 30 केडब्ल्यू एकीकृत संचालन प्रणाली का विकास इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भर भारत की ओर भारत के सफर में एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने यह भी बताया कि नई शुरू की गई 30 केडब्ल्यू एकीकृत संचालन प्रणाली इलेक्ट्रिक मोटर और इन्वर्टर को एक सिंगल कॉम्पैक्ट, हाई पावर-डेंसिटी यूनिट से जोड़ती है, जो पारंपरिक अलग मोटर-ड्राइव कॉन्फि गरेशन की जगह लेती है। उन्होंने कहा कि भारत में इस तरह के डिजाइन-आधारित नवोन्मेष से मजबूत घरेलू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाने, स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को तेज करने और ईवी क्षेत्र में हाई-वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

इस मौके पर सी-डैक के महानिदेशक श्री ई. मगेश; एमईआईटीवाई के ग्रुप कोऑर्डिनेटर (आईटी और सीसी और बीटी में आरऔरडी) श्री मनोज कुमार जैन; लुकास टीवीएस चेन्नई के सीटीओ श्री रामनाथन एन एस; सी-डैक, तिरुवनंतपुरम के सीनियर डायरेक्टर श्री रेनजी वी चाको; एमईआईटीवाई के वैज्ञानिक ह्यई' डॉ. ओम कृष्ण सिंह; आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर कमलेश हतुआ और उद्योग के प्रतिनिधि मौजूद थे।

वाणिज्य विभाग ने उभरते भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की

(एजेंसी)।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग ने उभरती भू-राजनीतिक स्थिति और निर्यात इकोसिस्टम सहित भारत के निर्यात-आयात (ईएक्सआईएम) कार्गो प्रवाह पर इसके संभावित प्रभाव की समीक्षा करने के लिए सभी हितधारक मंत्रालयों, प्रमुख लॉजिस्टिक्स और व्यापार सुविधा भागीदारों के साथ एक हितधारक परामर्श बैठक आयोजित किया।

वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव श्री सुचिंद्र मिश्रा और विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) श्री लव अग्रवाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इस बैठक में लॉजिस्टिक्स ऑपरेटरों और शिपिंग लाइनों/फॉरवर्डर्स, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, वित्तीय सेवा विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, निर्यात संवर्धन इकोसिस्टम और अन्य संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

हितधारकों ने बदलते परिचालन परिवेश का आकलन प्रस्तुत किया, जिसमें मार्गों और पारगमन समय में बदलाव, जहाजों के शेड्यूलिंग में समायोजन, कंटेनर/उपकरणों की उपलब्धता, माल ढुलाई और बीमा लागत के रुझान और समय के प्रति संवेदनशील निर्यात पर उनके प्रभावों की जानकारी दी गई। चर्चा में कार्गो आवाजाही में पूर्वानुमान बनाए रखने, अनावश्यक विलंब को कम करने और निर्यातकों व आयातकों के लिए निर्बाध दस्तावेजीकरण और भुगतान प्रक्रिया सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

विभाग ने आयात-निर्यात (ईएक्सआईएम) लॉजिस्टिक्स की निरंतरता सुनिश्चित करने और भारत के व्यापार प्रवाह में किसी भी व्यवधान को कम करने की भारत सरकार की प्राथमिकता को दोहराया। इस बात पर जोर दिया गया कि यह दृष्टिकोण सुगम और समन्वित बना रहेगा, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती बनाए रखने, निर्यातकों - विशेष रूप से एमएसएमई के हितों की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि घरेलू उत्पादन और उपभोग के लिए आवश्यक आयात पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

बैठक के दौरान हितधारकों के बीच मार्ग और क्षमता विकास, अधिभार और उपकरण उपलब्धता की वास्तविक समय में निगरानी के लिए निकट समन्वय बनाए रखने पर सहमति बनी। शीर्ष खराब होने वाले उत्पाद, औषधी तथा उच्च मूल्य के विनिर्मित निर्यात जैसे समय-संवेदी क्षेत्रों के लिए विशेष सुविधा तंत्र पर चर्चा की गई। बैठक में पत्तनों एवं अंतदेर्शीय कन्टेनर डिपो पर सुविधा सुदृढ़ करने तथा भीड़भाड़ एवं अधिक समय तक माल रुकने से बचाव पर बल दिया गया। सरकार ने व्यापारिक संचालन को सुगम बनाने के लिए अपनी तत्परता दोहराई, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: वास्तविक व्यवधान की स्थिति में निर्यात संबंधी अनुमतियों में प्रक्रियात्मक लचीलापन; सुचारू निकासी सुनिश्चित करने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ समन्वय; निर्यातकों के हितों की रक्षा के लिए वित्तीय और बीमा संस्थानों के साथ संवाद; निरंतर अंतर-मंत्रालयी समन्वय। विभाग ने इस बात को दोहराया है कि वह भारत के व्यापार को कुशलतापूर्वक संचालित करने और किसी भी उभरते मुद्दे का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।

युवा संगम (छठा चरण) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 2 मार्च, 2026 से शुरू होंगे

(एजेंसी)।

शिक्षा मंत्रालय ने "एक भारत श्रेष्ठ भारत" के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी युवा विनिमय कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए देश भर के 22 उच्च शिक्षा संस्थानों के युवाओं को आमंत्रित किया है। शिक्षा मंत्रालय ने आज एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी) पहल के तहत युवा संगम - चरण छः के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। 'युवा संगम' भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग का एक प्रमुख युवा विनिमय कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं के बीच भावनात्मक संबंधों को मजबूत बनाना और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। यह पहल युग्मित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सुनियोजित अनुभव यात्राओं के माध्यम से 'विविधता में एकता' की भावना को बढ़ावा देती है। 18-30 वर्ष की आयु वर्ग के इच्छुक युवा, जिनमें उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्र, एनएसएस/एनवाईकेएस स्वयंसेवक और युवा पेशेवर शामिल हैं, आधिकारिक पोर्टल https://ebsb.aicte-india.org और https://ekbharat.gov.in के माध्यम से आवेदन करने के पात्र हैं। पिछले युवा संगम चरण-पाँच में उल्लेखनीय भागीदारी देखी गई, जिसमें देश भर से 46,000 से अधिक पंजीकरण प्राप्त हुए। इसके शुभारंभ के बाद से, 6,000 से अधिक युवाओं और समन्वयकों ने युवा संगम के विभिन्न चरणों (2022 में आयोजित पायलट चरण सहित) जिनका आयोजन देश भर के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा किया गया, में गहन भ्रमण में भाग लिया है । यह अनुभवात्मक शिक्षा और राष्ट्रीय एकता के प्रति बढ़ते उत्साह को दर्शाता है।

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND OTHER PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER "NAVSARJAN SANSKRUTI" HINDI DAILY AS REQUIRED TO BE PUBLISHED UNDER RULE 8 OF REGISTRATION OF NEWS PAPER.
(CENTRAL RULES 1856)
FORM - IV
(SEE RULE - 8)

1.	Place of Publication	**538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh.**
2.	Periodicity of its publication	Gujarati Daily
3.	Printer's name	**(1) SUSHILA SHUKLA**
	Whether Citizen of India ?	Yes
	Address	**(1) Krishna Printiers,271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.**
4.	Publisher's name	**RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA**
		F/102,Tulsi Residency,Mansarover Road,IOC, **Chandkheda, Ahmedabad- 3802 424,Gujarat, India.**
5.	Editor's name	**VINOD KUMARI**
	Whether Citizen of India ?	Yes
	Address	**538 GHA/85** Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, **Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh.**
6.	Owners Names And Address	**RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA** **F/102,**Tulsi Residency,Mansarover Road,IOC, **Chandkheda, Ahmedabad- 3802 424,Gujarat, India.**

I **RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA** here by declare that particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date : 01-03-2026

Ragini Jigneshkumar Vaghela
Singaturs of Publisher.

आईएनएस सुदर्शिनी स्वेज नहर से महत्वपूर्ण यात्रा के बाद अलेक्जेंड्रिया पहुंचा

(एजेंसी)।

आईएनएस सुदर्शिनी 01 मार्च 2026 को ऐतिहासिक पोर्ट सिटी अलेक्जेंड्रिया पहुंचा, जो उसके चल रहे ट्रांसओशनिक अभियान, लोकायन-26 में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह जहाज पिछले हफ्ते सफागा से निकलने के बाद स्वेज नहर से उत्तर की ओर यात्रा करने के बाद पहुंचा है। तीन मस्तूल वाले बार्क का 193 किलोमीटर लंबी नहर से गुजरना- जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले दुनिया के ऐतिहासिक समुद्री मार्गों में से एक है- इस वैश्विक यात्रा में भाग लेने वाले प्रशिक्षुओं के लिए यह प्रशिक्षण का प्रमुख आकर्षण रहा है।

अलेक्जेंड्रिया में प्रवेश 'ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप' पहल को और मजबूत करता है, जो भारत और मिस्र के बीच लंबे समय से चली आ रही समुद्री साझेदारी का उत्सव मनाती है। दोनों देश कई सदियों से सांस्कृतिक संबंधों और आर्थिक संबंधों की एक समृद्ध विरासत साझा करते हैं। हाल के वर्षों में, रक्षा और समुद्री सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए हैं। सुदर्शिनी की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

जहाज के पहुंचने पर मिस्र की नेवी और भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने रिसीव किया। कमांडिंग ऑफिसर ने अलेक्जेंड्रिया नेवल बेस के कमांडर रियर एडमिरल महमूद अब्देलसत्तार से मुलाकात की। जहाज के ठहराव के दौरान, क्रू प्रोफेशनल एक्सचेंज, कम्युनिटी आउटरीच और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य आपसी सद्भावना बढ़ाना, इंटरऑपरेबिलिटी को मजबूत करना और दोनों नौसेनाओं

के बीच सहयोग बढ़ाना है।

लखनऊ में युवराज सिंह ने लड़कियों को सिखाए क्रिकेट के गुर, संघर्ष के दिनों को याद किया

लखनऊ में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने उभरते हुए क्रिकेट खिलाड़ियों को बल्लेबाजी और गेंदबाजी के महत्वपूर्ण टिप्स शेयर किए.

(एजेंसी)।

लखनऊः भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह ने सोमवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में महिला क्रिकेटरों को विशेष प्रशिक्षण दिया. इस दौरान उन्होंने महिला डगआउट का उद्घाटन किया और ग्रासरूट स्तर के खिलाड़ियों को खेल के प्रति प्रेरित किया. यह प्रोग्राम एक निजी संस्था द्वारा क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था. युवराज सिंह ने

उभरते हुए खिलाड़ियों को बल्लेबाजी और गेंदबाजी के महत्वपूर्ण टिप्स शेयर किए.

बल्लेबाजी की तकनीक सिखायीः युवराज सिंह ने बड़े हिट्स लगाने की तकनीक बताई और स्पिन व पेस गेंदबाजी के दौरान सही लाइन-लेंथ, बॉडी पोस्चर और रिलीज पॉइंट के बारे में विस्तार से मार्गदर्शन किया. युवराज के निर्देशन में खिलाड़ियों ने नेट पर बैटिंग और बॉलिंग का कड़ा अभ्यास किया. उन्होंने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जैसे युवा सितारों का उदाहरण देते हुए कहा कि टैलेंट के साथ सही मार्गदर्शन बेहद जरूरी है. अपनी करियर की चुनौतियों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि मुश्किल समय में सचिन तेंदुलकर की सलाह ने उनके लिए चीजें स्पष्ट कर दी थीं. संघर्ष के दिनों की यादें शेयर कीं: एक सवाल के जवाब में युवराज ने गर्व से कहा कि वह तीन बार के वर्ल्ड कप विजेता हैं और हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं. उन्होंने चिंता जताई कि कई बच्चे संसाधनों और किट की कमी के कारण क्रिकेट छोड़ देते हैं, जिसे वह अपनी एकेडमी के जरिए दूर करने का प्रयास कर रहे हैं.

560 अमेरिकी सैनिक ढेर, कई एयरबेस तबाह! ईरान के पलटवार से बर्बाद हुआ अमेरिका, टेंशन में ट्रंप

(एजेंसी)।

ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जारी युद्ध ने अब एक ऐसा रुख अख्तियार कर लिया है, जिसने पेंटागन की रातों की नींद उड़ा दी है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के हालिया दावों ने वैश्विक सैन्य संतुलन को हिलाकर रख दिया है। ईरान का दावा है कि उसने न केवल अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, बल्कि सुपरपावर अमेरिका को वह 'बड़ा झटका' दिया है जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी।

मध्य पूर्व में अमेरिका के अभेद्य माने जाने वाले सुरक्षा चक्र को भेदते हुए ईरान ने उसकी नौसैनिक और हवाई ताकत को सीधी चुनौती दी है। दावों के अनुसार, अमेरिकी एयरबेस अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके हैं, जिससे क्षेत्र में वाशिंगटन का दबदबा खतरे में पड़ता दिख रहा है।

सबसे चौंकाने वाला दावा 560 अमेरिकी सैनिकों के हताहत होने का है। इसके साथ ही, समुद्र में अमेरिका की शान माने जाने वाले विमानवाहक पोत 'अब्राहम लिंकन' पर चार बैलिस्टिक मिसाइलें दागने की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। अगर ये दावे पुख्ता होते हैं, तो यह आधुनिक इतिहास में अमेरिकी नौसेना को लगा अब तक का सबसे बड़ा और घातक झटका साबित होगा।

ईरान ने दावा किया है कि उसने कुवैत में स्थित अमेरिकी नौसैनिक एयरबेस को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है, जिसके बाद उसे बंद करना पड़ा। इसके अलावा, बहरीन में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर भी ड्रोन और मिसाइलों की बारिश कर भारी नुकसान पहुँचाया गया है। इन हमलों ने मध्य पूर्व में अमेरिका के पूरे लॉजिस्टिक और डिफेंस नेटवर्क को पंगु बनाने की कोशिश की है।

ये भी पढ़ें; अ' डौँल्ल्री के बाद कौन बनेगा ईरान का नया सुप्रीम लीडर? सत्ता की रेस में दो बड़े नाम आगे

सीएम नायब सिंह सैनी ने 2.23 लाख करोड़ का बजट पेश किया, प्वाइंट में समझें बड़े ऐलान

(एजेंसी)।

हरियाणा के मुख्ं यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार (2 मार्च, 2026) को हरियाणा विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री के रूप में यह उनका दूसरा बजट था। सीएम सैनी ने 2,23,658.17 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित करते हुए महिलाओं, किसानों और छात्रों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं।

इसके साथ ही राज्य के समग्र और संतुलित विकास को ध्यान में रखते हुए कृषि, शिक्षा, रोजगार, उद्योग और बुनियादी ढांचे से जुड़ी नई योजनाओं का भी ऐलान किया। वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने का प्रस्ताव भी रखा गया है।

बजट पूर्व परामर्श से प्राप्त 5000 सुझावों को बजट प्रस्ताव में शामिल किया गया।

राज्य सरकार के कुल राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत केंद्रीय करों से मिलने वाला हिस्सा है।

16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वर्ष 2026 से 2031 तक हरियाणा का केंद्रीय करों में हिस्सा 1.361% रहेगा।

विश्व बैंक के बोर्ड ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए 'हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट' को स्वीकृति दी।

वर्ष 2031 तक सभी जिलों में लागू होने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक द्वारा 2716 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी।

वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा GDP का 2.66% रहने का अनुमान, जिसे वर्ष 2026-27 में घटाकर 2.65% तक सीमित रखने का प्रस्ताव।

वर्ष 2025-26 के लिए कुल बजट 2,50,017 करोड़ रुपये रखा गया, जिसमें 31 मार्च 2026 तक लगभग 2,20,000 करोड़ रुपये व्यय अनुमानित।

वर्ष 2026-27 के लिए कुल 2,23,658.17 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।

बजट में 4293.17 करोड़ रुपये का राजकोषीय घाटा (GDP का 2.65%), राजस्व घाटा 0.87%, प्रभावित राजस्व घाटा 0.41%, पूंजीगत व्यय 1.86% और प्रभावी पूंजीगत व्यय 2.32% प्रस्तावित।

तो इसलिए खामेनेई को ट्रंप ने उतारा मौत के घाट, अब आई असली वजह सामने, फोन पर पत्रकार को खुद बताई सच्चाई

(एजेंसी)।

अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग का तीसरा दिन मिडिल ईस्ट के लिए बेहद तनावपूर्ण रहा। इसी बीच एक बड़ा राजनीतिक धमाका तब हुआ जब अमेरिकी पत्रकार जोनाथन कार्ल (खङ्मल्लं३ँल्ल डं१') ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधे सवाल किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के पीछे असली वजह क्या थी। ट्रंप का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने साफ कहा, "उसने (डौँल्ल्री) मुझे दो बार मारने की कोशिश की थी, मैंने उसे पहले मार दिया।"

अइउ ठी६२ के वॉशिंगटन चीफ कॉरेस्पोंडेंट नाथन कार्ल ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने ईरान को लेकर ट्रंप से कई मिनट तक बातचीत की। उन्होंने ट्रंप से पूछा कि जब खामेनेई नहीं रहे तो अब सत्ता कौन संभालेगा। इस पर ट्रंप ने कहा कि हमला बेहद सटीक और सफल था। उनके मुताबिक, कई वरिष्ठ अधिकारी और संभावित उत्तराधिकारी मारे जा चुके हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि जिन नामों पर चर्चा हो रही थी, वे सभी अब जिंदा नहीं हैं। यानी सत्ता की अगली लाइन लगभग खत्म हो चुकी है।

जोनाथन कार्ल ने यह भी बताया कि उन्होंने ट्रंप से 2024 में कथित ईरानी साजिश का जिक्र किया, जिसमें ट्रंप की हत्या की कोशिश की बात सामने आई थी। इस पर ट्रंप ने कहा, "उन्होंने मुझे दो बार मारने की कोशिश की। इससे पहले कि वो मुझे मारता, मैंने उसे मरवा दिया।" ट्रंप का यह बयान अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के उन दावों से जुड़ा है, जिनमें कहा गया था कि ईरान की सरकार ट्रंप के खिलाफ साजिश रच रही थी।

किस मुस्लिम दोस्त के कहने पर ट्रंप ने ईरान पर किया हमला? आते थे प्राइवेट कॉल, नेता का नाम चौंका देगा

किस मुस्लिम दोस्त के कहने पर ट्रंप ने ईरान पर किया हमला? आते थे प्राइवेट कॉल, नेता का नाम चौंका देगा

अमेरिकी पत्रकार जोनाथन कार्ल की ट्रंप से फोन पर हुई बातचीत

एक्स पर शेयर किए वीडियो में जोनाथन कार्ल कहते हैं,

"मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से ईरान को लेकर कई मिनट तक बात की। मैंने उनसे पूछा कि अब जब अयातुल्ला अली खामेनेई, जो सुप्रीम लीडर थे, नहीं रहे तो अब उनकी जगह कौन लेगा? उनका (ट्रंप) जवाब दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि हमला इतना सफल रहा कि ज्यादातर संभावित दावेदार ही खत्म हो गए। उन्होंने मुझसे कहा कि अब वह कोई भी नहीं होगा जिसके बारे में हम सोच रहे थे, क्योंकि वे सभी मारे जा चुके हैं। मैंने उनसे इस बात पर भी चर्चा की कि ईरानियों ने उन्हें मारने की कोशिश की थी। 2024 में ट्रंप को मारने की एक ईरानी साजिश थी। इस पर उन्होंने अयातुल्ला के बारे में कहा, 'मैंने उसे उससे पहले खत्म कर दिया, इससे पहले कि वह मुझे खत्म करता। उन्होंने दो बार कोशिश की। खैर, मैंने उसे पहले ही मार दिया।' जहां तक युद्ध कितने समय तक चलेगा, इस सवाल पर राष्ट्रपति ने मुझसे कहा कि उन्हें हमेशा लगता था कि यह चार या पांच हफ्तों का मामला होगा। उन्होंने यही कहा, चार या पांच हफ्तों का ऑपरेशन। उन्होंने कहा कि यह इससे छोटा भी हो सकता है और जरूरत पड़ी तो वह इसे लंबा चलाने के लिए भी तैयार थे। तीन अमेरिकियों की मौत पर राष्ट्रपति ने कहा, 'यह युद्ध है और युद्ध में हताहत होते हैं।' उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि राष्ट्रपति के तौर पर वेनेजुएला में किए गए ऑपरेशन, पिछले गर्मियों में ईरान में किए गए ऑपरेशन और इस मौजूदा ऑपरेशन के बावजूद, अब तक कुल अमेरिकी हताहतों की संख्या सिर्फ तीन है। आज रात राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई लंबी बातचीत का यह एक संक्षिप्त सार है।"

ऑपरेशन 'एपिक फ्यूरी' और बढ़ता टकराव (डस्री१ं३ङ्मल्ल एस्रू

अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एयरस्ट्राइक की। अमेरिका ने इस मिशन को 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' नाम दिया। इस अभियान में ईरान के कई सरकारी और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसी हमले में खामेनेई सहित कई शीर्ष राजनीतिक और सैन्य चेहरे मारे जाने का दावा किया गया।

इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई तेज कर दी। मिसाइल हमले इजराइल की ओर दागे जा रहे हैं और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया जा रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट में हालात विस्फोटक बने हुए हैं।

ट्रंप का यह दावा कि खामेनेई ने उन्हें दो बार मारने की कोशिश की थी और इसी वजह से उन्होंने पहले कार्रवाई की, इस जंग को और राजनीतिक रंग दे रहा है। अगर यह बयान सही है तो यह सिर्फ सैन्य टकराव नहीं, बल्कि निजी और रणनीतिक प्रतिशोध की कहानी भी बन सकता है। फिलहाल सवाल यही है कि क्या यह चार-पांच हफ्तों में खत्म होगा या मिडिल ईस्ट एक लंबी और

जूडो खिलाड़ियों ने लखनऊ में जीते चार पदक

(एजेंसी)।

गढ़मुक्तेश्वर। नगर के शाहपुर मार्ग पर स्थित देव-आदित्य मेमोरियल जूडो अकादमी में सोमवार को प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ। इसमें प्रदेश स्तरीय समन्वय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।

लखनऊ, (एजेंसी)। जूडो प्रशिक्षक सुबोध यादव ने बताया कि लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 25 से 27 फरवरी तक प्रदेश स्तरीय समन्वय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें विभिन्न भार वर्गों में बालक और बालिकाओं की प्रतिस्पधाएं हुई। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में देव-आदित्य मेमोरियल जूडो अकादमी के खिलाड़ियों ने मेरठ मंडल का प्रतिनिधित्व करते हुए शानदार प्रदर्शन किया।

गांव सिकंदरपुर निवासी नव्या यादव ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर क्षेत्र का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया। इसके अलावा सिकंदरपुर निवासी भास्कर ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में रजत, करीमपुर निवासी यशी ने 32 किलोग्राम भार वर्ग का रजत पदक अपने नाम किया। वहीं, करीमपुर की ही रहने वाली अंशिका ने 28 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता।

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने मेरठ मंडल की टीम को ओवरऑल चैंपियनशिप जिताने में अहम भूमिका निभाई। खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हुए डीएम पब्लिक स्कूल के प्रबंधक राजेंद्र सिंह ने कहा कि जूडो केवल एक खेल नहीं है, यह आत्मरक्षा का भी बेहतरीन साधन है। इस खेल के माध्यम से बच्चे अनुशासित होने के साथ ही मजबूत भी बनते हैं। अनुशासन और निरंतर अभ्यास ही सफलता के लिए जरूरी हैं।

भारत-कनाडा ने लिखा दोस्ती का नया अध्याय

(एजेंसी)।

भारत और कनाडा के राजनयिक संबंधों में एक नया और सकारात्मक अध्याय शुरू हुआ है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की पहली भारत यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी ने इस मुलाकात को दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव करार देते हुए कहा कि यह यात्रा पिछले साल जी7 बैठक के दौरान बनी आपसी सम्मान और गर्मजोशी की भावना को दोहराती है।

यह ऐतिहासिक दौरा आपसी विश्वास और सकारात्मक सोच पर आधारित है, जिसने दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच सहयोग को एक नई दिशा प्रदान की है। दोनों नेताओं ने विविधता में विश्वास और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों को रेखांकित करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने की प्रतिबद्धता जताई है।

2030 तक व्यापार का विशाल लक्ष्य

दोनों देशों ने आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने पर सहमति बनी है, जो व्यापार बाधाओं को कम करेगा और निवेश के नए अवसर पैदा करेगा।

पीएम मोदी ने भारत की आर्थिक प्रगति में कनाडा के विश्वास की सराहना करते हुए बताया कि कनाडाई पेंशन फंड पहले ही भारत में लगभग 100 अरब डॉलर का निवेश कर चुके हैं। यह निवेश भारत के बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं में गहरे भरोसे का संकेत है।

तकनीक और नवाचार में सहयोग

तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में शामिल हैं:

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)

क्वांटम टेक्नोलॉजी

सुपरकंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर

इसके अतिरिक्त, भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बीच तकनीक सहयोग को लेकर एक त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ है, जो वैश्विक नवाचार में इन देशों की भूमिका को मजबूत करेगा।

ऊर्जा और परमाणु सुरक्षा में बड़ी प्रगति

ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, कनाडा ने इंटरनेशनल सोलर एलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस से जुड़ने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस वर्ष भारत-कनाडा रिन्यूएबल एनर्जी और स्टोरेज समिट का आयोजन किया जाएगा।

नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, दीर्घकालिक यूरेनियम आपूर्ति को लेकर एक अहम समझौता हुआ है, जो भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा। दोनों देश छोटे और उन्नत परमाणु रिएक्टर पर भी मिलकर काम करेंगे।

रक्षा और सुरक्षा साझेदारी

रक्षा उद्योग और समुद्री निगरानी को बढ़ावा देने के लिए, दोनों देशों ने भारत-कनाडा रक्षा संवाद शुरू करने का निर्णय लिया है। यह संवाद सैन्य आदान-प्रदान और सुरक्षा सहयोग को और अधिक गहरा बनाएगा।

सांस्कृतिक और शैक्षिक रिश्ते

लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। कनाडा के विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस खोलने पर सहमत हुए हैं, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में नई साझेदारी की शुरूआत होगी।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए समझौते हुए हैं, जिसमें आदिवासी और मूल समुदायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति बनी है। कृषि क्षेत्र में, इंडिया-कनाडा पल्स प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, जो दोनों देशों के कृषि नवाचार को मजबूती देगा।

'बेहतर होगा कि सरेंडर कर दे ईरान', ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी, बोले- लंबा चलेगा ऑपरेशन

(एजेंसी)।

पश्चिम एशिया में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। 28 फरवरी को इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में खुला सैन्य टकराव शुरू हो गया है। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और उनके परिवार के कई सदस्य मारे गए।

इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और सहयोगी देशों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। युद्ध अब तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। संयुक्त हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई, उनकी बेटी, पोते/नाते, बहू और दामाद की मौत हो गई। उनकी पत्नी, जो हमले में गंभीर रूप से घायल हुई थीं, ने भी बाद में दम तोड़ दिया।

ईरान-अमेरिका-इजरायल टकराव अब पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में लेता दिख रहा है। इसी बीच अमेरिका के राष्ं ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी चेतावनी दी है।

ट्रंप की कड़ी चेतावनी - "ईरान के लिए बेहतर होगा सरेंडर कर दे

युद्ध के तीसरे दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चला रहा है और उसका मुख्य लक्ष्य ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करना है। ट्रंप ने कहा कि कार्रवाई के लिए यही सही मौका था। उनका आरोप था कि ईरान लगातार सच छिपा रहा है और गुमराह कर रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि उसके खिलाफ लंबा अभियान चलाया जाएगा, जिसे पूरी दुनिया देखेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान के लिए बेहतर यही होगा कि वह आत्मसमर्पण कर दे।

ट्रंप बोले- ईरान को परमाणु ताकत बनने नहीं दे सकते

ईरान ने कहा कि ईरान के पास लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता मौजूद है और यदि उसे परमाणु हथियार मिल जाता है तो यह अमेरिकी नागरिकों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। उनका कहना था कि किसी ऐसे देश को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती, जिस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हों। उनके मुताबिक, यदि ईरान के पास ऐसा हथियार हुआ तो वह इसका इस्तेमाल दुनिया पर दबाव बनाने और अपनी शर्तें मनवाने के लिए कर सकता है।

ईरान ने चेतावनी को किया नजरअंदाज

ट्रंप ने कहा, "मैंने हमला करने से पहले ईरान को समझाया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होगा तो वह अमेरिकियों के लिए गंभीर खतरा बन जाएगा। हम ऐसे देश को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दे सकते।"

"ऑपरेशन 4-5 हफ्ते चल सकता है"

ट्रंप ने संकेत दिए कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान 4 से 5 सप्ताह तक चल सकता है, हालांकि अमेरिका इससे ज्यादा समय तक कार्रवाई के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अमेरिका यह सुनिश्चित करेगा कि ईरानी शासन अपनी सीमाओं के बाहर आतंकवादी संगठनों को हथियार और वित्तीय सहायता न दे सके। उन्होंने दावा किया कि पहले एक समझौता लगभग तय हो गया था, लेकिन ईरान पीछे हट गया।

ओबामा पर पर भी निशाना

पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर हमला करते हुए ट्रंप ने कहा कि उनके कार्यकाल में किया गया समझौता "मूर्खतापूर्ण" था और उससे ईरान को कानूनी रूप से परमाणु हथियार हासिल करने की राह मिल सकती थी। ट्रंप ने दोहराया कि उनके नेतृत्व में अमेरिका इस खतरे को समाप्त करेगा।

जमीनी सैनिक भेजने से इनकार नहीं

न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए बयान में ट्रंप ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो ईरान में अमेरिकी जमीनी सैनिक भी भेजे जा सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने अपेक्षा से कहीं तेज कार्रवाई की है और आगे "बड़ी लहर" आने वाली है। CNN से बातचीत में ट्रंप ने कहा, "हमने उन पर जोरदार मार करना शुरू भी नहीं किया है।

ब्लॉकबस्टर फिल्म 'मंजुम्मेल बॉयज' के डायरेक्टर चिदंबरम एस पोडुवाल पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप, केस दर्ज

(एजेंसी)।

सुपरहिट मलयालम फिल्म 'मंजुम्मेल बॉयज' के डायरेक्टर Chidambaram S Poduval के खिलाफ केरल में यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कोच्चि की एनार्कुलम साउथ पुलिस ने एक महिला की शिकायत के आधार पर रविवार को केस दर्ज किया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह शिकायत 2022 की एक कथित घटना से जुड़ी है। महिला ने आरोप लगाया है कि डायरेक्टर ने एलामकुलम स्थित उसके अपार्टमेंट में जबरन घुसकर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 और 75 के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता का बयान दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच के तहत डायरेक्टर को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जाएगा।

निर्देशक की ओर से अभी कोई बयान नहीं

चिदंबरम एस पोडुवाल मलयालम

फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने निर्देशक और लेखक हैं। उन्होंने 2021 में 'जन.ई.मैन' का निर्देशन किया था। लेकिन उन्हें असली पहचान 'मंजुम्मेल बॉयज' से मिली। फिलहाल, इस मामले पर उनकी ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता

'मंजुम्मेल बॉयज' मलयालम सिनेमा की बड़ी हिट फिल्मों में से एक है। इस फिल्म ने 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की और सर्वाधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्मों में शामिल हो गई। इसने पहले रिलीज हुई फिल्म '2018' का रिकॉर्ड भी तोड़ा था। बाद में 'L2: एम्पुरान' ने इसे पीछे छोड़ दिया। फिल्म को क्रिटिक्स ने भी खूब पसंद किया था। जिसके बाद इसे वर्ड ऑफ माउथ का फायदा भी मिला था।

अवॉर्ड्स में भी मिली पहचान

फिल्म में सौबिन शाहीर, श्रीनाथ भासी, दीपक परंबोल, बालू वर्गीज, गणपति एस पोडुवाल और लाल जूनियर जैसे कलाकार नजर आए थे। इसे 55वें केरल स्टेट फिल्म अवॉर्ड्स में 10 पुरस्कार मिले। साथ ही 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स साउथ में इसे सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म का खिताब भी मिला।

फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगे की कार्रवाई पूछताछ और सबूतों के आधार पर तय की जाएगी।